पेश में 20 शीर्षस्थ आयकर दाता

64. **श्री शकर दयाल सिंह :** क्या **वित्त** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) देश मे 20 शीर्षस्थ आयकर दाताओ के नाम क्या है ,

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान इन्होने कुल कितना आयकर अदा किया है, और

(ग) उन 20 व्यापारिक घरानो और व्यक्तियो के नाम क्या-क्या है जिनकी और इस समय आयकर के रूप मे 25 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है ?

वित्त मत्रालय में उपमत्री और विदेश मत्रालय में उपमत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जिन 20 करदाताओ की तरफ दिनाक 30-6-1990 की स्थिति के अनुसार आयकर की अधिकतम माग बकाया थी, उनके नामो को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सलग्न है (**नीचे** देखिए) । तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी तरफ बकाया माग का एक बडा भाग अपीलो आदि से विवादग्रस्त है । कुछ मामलो मे, अदा किए गए कर/ बकाया वापस अदायगियो के परिशोधन अथवा समायोजन हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन पडे हुए है।

विवरण

क्रम स.	कर-निर्धारिती का नाम
1	मैसर्स जी. टी. सी. इडस्ट्रीज लिमिटेड
2	मैसर्स इडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
3	मैसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
4	मैसर्स डनलप इडिय लि.
5	मैसर्स वैस्टर्न कोल फील्ड लि.
6	मैसर्स काटीनेंटल कास्ट. लि.
7	मैसर्स मोदी रबड लि.
8	मैसर्स आर्सन इलैक्ट्रॉनिक्स लि.
9	मैसर्स जै के. सिन्थेटिक्स लि.
10	श्री डब्ल्यू. एन चड्ढा
11	मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि.
12	मैसर्स युनाइटेड बैंक आफ इडिया
13	मैसर्स हृदयी कारपो एवं एच. एच आई के अभिकर्त्ता के रूप मे मैसर्स तेल एव प्रा तिक गैस आयोग
14	मैसर्स एस कॉर्टस लि
15	श्री विनोद कुमार डिडवानिया
16.	मैसर्स इटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इडिया
17	मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इडिया लि.
18	मैसर्स मोदी पान लि.
19	श्री सुकरभाई एन. बाख्या
20	मैसर्स आई. सी. आई. सी. आई. लि.

टिप्पणी . मैसर्स आई. टी सी. लिमिटेड के मामले मे लगभग 64. 58 करोड रुपये की माग जारी की गई थी किन्तु माग-नोटिस तामील किए जाने से पूर्व ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभाग को कर-निर्धारण विषयक आदेशो को तथा माग-नोटिसो को तामील करने से रोकते हुए अन्तरिम व्यादेश पारित कर दिया । इसलिए, इस मामले को उक्त सूची मे शामिल नही किया गया है।

Nationa ised Banks identified as Sick by RBI

65 SHRI CHIMANBHAI MEHTA Will the Minister of FINANCE be pleased to state·

(a) whether it is a fact that a number of nationalised banks in the country have